Central Chronicle 4 January, 2018

Union Budget 2018-19: ASSOCHAM seeks venture capital pool & lower tax rates for electronics sector

Agencies, Kolkata

Considering that costs pertaining to finance, energy and logistics/transportation constitute major portion of consumer electronics sector, apex industry body ASSOCHAM has recommended the union government to allow weighted deduction of 150-200 per cent of the actual cost on specified components.

"Further, these costs are auditable and duly included in the financial statements of a company," noted the ASSOCHAM pre-budget recommendations on direct taxes submitted to the Centre.

With a view to revive private investments in the electronics sector, ASSOCHAM has suggested that venture capital pool may be initiated and coordinated by a bank/special purpose vehicle (SPV) or under public-private partnership (PPP) mode.

"While contributors may be offered tax incentives on the dividend, manufacturers may be provided with tax exemptions," it said.

"In order to boost the availability of capital funds to India's $100 billion worth electronics industry, it is imperative that a venture capital pool be created and allied tax incentive provided to enable genuine private players to use funds of such pool through a stringent mechanism,"ASSOCHAM secretary general D S Rawat today said.

To further make the business competitive in the electronics sector, ASSOCHAM has recommended the government to link the India BPO Promotion Scheme (IBPS) with direct tax benefit.

"The government should allow assesses to claim depreciation on assets funded by government subsidy under the IBPS scheme."

It added that government did not receive expected response under this scheme – one reason could be that overall benefit under this scheme will be reduced by 33 per cent as the assesses cannot claim depreciation on assets funded by the government subsidy.

DB Post 4 January, 2018

Reduce taxes on electronic goods: Industry

New Delhi: Industry body Assocham on Wednesday recommended a weighted tax deduction of 150-200 per cent on actual cost of specified components for the consumer electronics sector in the upcoming Union Budget.

The deduction is required as costs pertaining to finance, energy and logistics/transportation constitute a major portion of consumer electronics sector, the chamber said. "Further, these costs are auditable and duly included in the financial statements of a company," the release said quoting the recommendations on direct tax made by the body to the centre.

With a view to revive private investments in electronics sector, Assocham has suggested venture capital pool may be introduced in the sector and coordinated by a bank/special purpose vehicle or under public-private partnership mode, according to the release. "It will boost availability of capital funds to India's $100 billion worth electronics industry.

Deshbandhu 4 January, 2018

एसोचैम ने की इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कम कर की मांग

नई दिल्ली, 3 जनवरी (एजेंसियां)। उद्योग मंडल एसोचैम ने बुधवार को आगामी आम बजट में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विनिर्दिष्ट घटकों की वास्तविक लागत पर 150-200 फीसदी की भारित कर कटौती की सिफारिश की है।

मंडल ने यहां एक बयान जारी कर कहा, करों में कटौती की आवश्यकता है क्योंकि वित्त, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स/परिवहन से संबंधित लागत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। बयान में मंडल द्वारा केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर पर की गई सिफारिश के हवाले से कहा गया, इसके अलावा, ये लागत लेखा परीक्षण योग्य है और कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट में भी इनका विधिवत उल्लेख होता है। बयान के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निजी निवेश में तेजी वापस लाने के लिए एसोचैम ने क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल पूल बनाने की सलाह दी है, जिसका समन्वय किसी बैंक/स्पेशल पपर्ज वेहिकल द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत किया जा सकता है। एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने कहा कि भारत के 100 अरब डॉलर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पूंजीगत वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि एक वेंचर कैपिटल पूल का निर्माण किया जाए। बयान में कहा गया कि इस पूल में योगदान करने वालों को लाभांश पर कर प्रोत्साहन दिया जाए, जबकि निर्माताओं को कर में छूट दी जाए।

Punjab Kesari 4 January, 2018

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कम कर की मांग

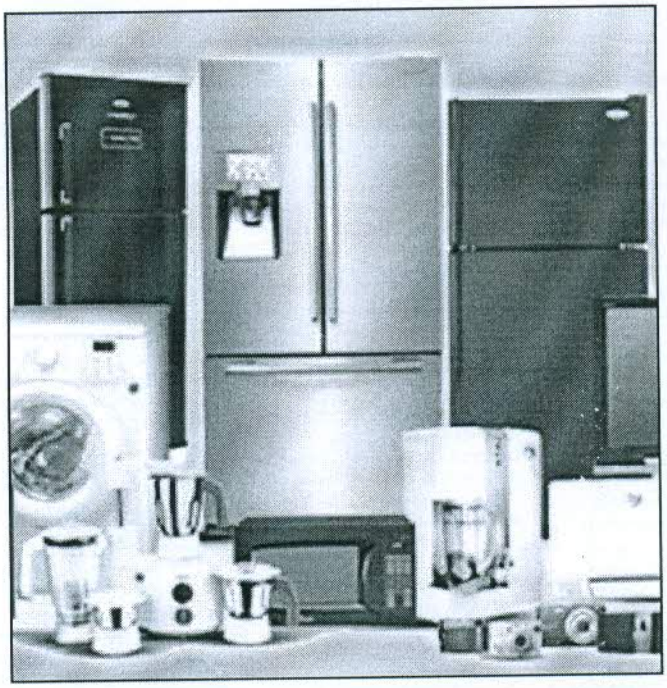

नई दिल्ली, (आईएएनएस): उद्योग मंडल एसोचैम ने बुधवार को आगामी आम बजट में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विनिर्दिष्ट घटकों की वास्तविक लागत पर 150-200 फीसदी की भारित कर कटौती की सिफारिश की है। मंडल ने यहां एक बयान जारी कर कहा, करों में कटौती की आवश्यकता है क्योंकि वित्त, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स/परिवहन से संबंधित लागत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। बयान में मंडल द्वारा केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर पर की गई सिफारिश के हवाले से कहा गया, इसके अलावा, ये लागत लेखा परीक्षण योग्य है और कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट में भी इनका विधिवत उल्लेख होता है। बयान के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निजी निवेश में तेजी वापस लाने के लिए एसोचैम ने क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल पूल बनाने की सलाह दी है, जिसका समन्वय किसी बैंक/स्पेशल पपर्ज वेहिकल द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत किया जा सकता है।